

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,

प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

देहरादून।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: ०४ अप्रैल, 2008

विषय:- एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड को तहसील विकासनगर परगना पछवाडून के ग्राम कोल्हूपानी में कुल 5.099 है० भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपे पत्र संख्या- 1687/12ए-89 (2005-08) दिनांक 1 फरवरी, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या- 258/16 (1)/73-रा-1 दिनांक 09 मई, 1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1 -1(60)/93-रा-1 दिनांक 12-9-97 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तहसील विकासनगर परगना पछवाडून, ग्राम कोल्हूपानी के खाता 307 के खसरा नं० 208घ रकबा 0.020 व 214क रकबा 4.488 नदी श्रेणी व खाता संख्या 300 के खसरा नम्बर 208ग रकबा 0.437 व 214घ रकबा 0.154 पुरानी परती की भूमि है। जिसका कुल क्षेत्रफल 5.099 है० भूमि वर्तमान बाजार दर की दोगुने से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत कर एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड, नई दिल्ली को एयरफोर्स व नेवी के सेवकों के लिए आवासीय भवन बनाये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
- (2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

24

.....(2)

- (3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकार सम्पत्ति के प्रबंध से सम्बन्धित शारानादेश संख्या-150/1/85(24)-रा0-6 दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।
- (4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।
- (5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, अथवा आर्गेनाइजेशन (संस्था) का विघटन हो गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
- (6) भूमि आवंटन से पूर्व नियमानुसार श्रेणी परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।
- (7) आवासीय कालोनी के निर्माण के पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी/विभाग की अनापत्ति (अनापत्तियों) प्राप्त कर ली जायेंगी। इसके अतिरिक्त इस भूमि में से भूखण्ड या भवन आवंटन का समस्त दायित्व एवं जिम्मेदारी भी संस्था की होगी।
- (8) आवंटित भूमि का प्रयोग संस्था द्वारा सेवारत एवं पूर्व सैनिकों के लिये आवासीय भवन के निर्माण हेतु ही किया जायेगा।
- (9) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु सं० 1 से 8 तक की किराी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी। जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- 2- उक्त आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन०एस० नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

.....(3)

- 2- राधिव, रौनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- डायरेक्टर जनरल, एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड, एयर फोर्स स्टेशन, नई दिल्ली, 110003.
- ✓ 5- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से.
(सन्तोष बड़ानी)
अनुसचिव।